



६

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रापिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

लं. 240]

नई विल्ली, बृहस्पतिवार, मई 17, 1984/वैशाख 27, 1906

No. 240]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 17, 1984/VAISAKHA 27, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी आती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई विल्ली, 11 मई, 1984

का० आ० 389(अ):—कलिप्य नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे बेंक्रीय भरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाना चाहती है, उस धारा की उपचारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की जनकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उमसे प्रभावित होने की सम्भावना है। इसके द्वारा यह सूचना वी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उक्त अधिसूचना बाला राजपत्र जनकार को उपलब्ध कराएं जाने की शरीख से माठ दिन की समाजिक पश्चात विवार किया जाएगा।

ऐसे आक्षेपों या सुनावों पर जो इस प्रकार विनिर्विट अवधि के भीतर उक्त प्रारूप की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार विवार करेगी।

ऐसे आक्षेप या सुनाव, सचिव, उद्योग मंत्रालय (भारी उद्योग विभाग) उद्योग भवन, नई विल्ली-110011 के पते पर भेजे जाने चाहिए।

प्रारूप नियम:

- संक्षिप्त नाम—इन नियमों का संक्षिप्त नाम मोटरगाड़ी उपकर नियम, 1984 है।
- परिभाषाएँ—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:—
 - (क) “अधिनियम” से उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) अन्तिम है;
 - (ख) “उपकर” से अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन आरी की गई भारी उद्योग विभाग की अधिसूचना सं० का० आ० 932 (अ) तारीख 28-12-1983 के निवंधनों के अनुसार बदली गई है;
 - (ग) “कलक्टर” से केंद्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर अन्तिम है और इसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपर कलक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क उपकलक्टर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क सहायक कलक्टर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक सम्मिलित हैं;
 - (घ) “विकास परिषद” से अधिनियम की धारा 6 के अधीन स्थापित मोटर गाड़ी और महबूद उद्योग विभाग परिषद अन्तिम है;
 - (इ) “मोटर गाड़ी” से अन्तिम है मोटरकार, बसें, ट्रक, जीप प्रकार के यान, बैन, स्कूटर, मोटर साईकिल, मोड़ह और सभी अन्य मोटर गाड़ियां जो अधिनियम की पहली अनुसूची के उपरीबंद (5) के अन्तर्गत आती हैं;

(c) उन शब्दों और पदों के, जिनका हमें प्रयोग किया गया है और जिनकी परिभ्रषा नहीं दी गई है, किन्तु जिनकी परिभाषा केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) या उसके अधीन बनाए गए नियमों में दी गई है, वही अर्थ होते जो उसके क्रमशः उस अधिनियम या नियमों में है।

3. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का लागू होना—इन नियमों में अन्यथा उत्पादित के विवाद, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों, जिनमें वे भी सम्मिलित हैं जो शुल्क के प्रतिवाद से संबंधित हैं, उपकर के उद्ग्रहण और सग्रहण के संबंध में वहाँ तक लागू होती जहाँ तक वे उस अधिनियम और नियमों के अधीन मोटर गाड़ियों के विनियमित पर उत्पाद-शुल्क के उद्ग्रहण और सग्रहण के संबंध में लागू होते हैं।

4. किन्तु ये कांडे का प्रमुख किया जाता—(1) प्रत्येक विनियमीता, कलकटा और विकास परिषद के समक्ष प्रत्येक मास की दस तारीख को या उसके पूर्व, पूर्वजर्ती मास के दौरान अपने उपकर में विनियमित या उत्पादित और वहाँ से हटाए गए मोटर गाड़ियों की सदों के मध्य स्टॉक की विवरणी, इन नियमों के उत्पादित में विनियित प्रक्रिया में प्रस्तुत करेगा।

(2) परि कोई विनियमित उपनियम (1) में विनियित तारीख के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है या ऐसी विवरणी प्रस्तुत करता है जिसके बारे में कलकटा या विकास परिषद को यह विष्वास करने का कारण हो कि वह टक्की नहीं है या लूटपूर्ण है तो कलकटा, विनियमित या उत्पादित मोटर गाड़ियों से संबंधित या विनियमित तारीख के अनुसार तैयार किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जरूर किए जाएं।

5. उपकर के आगम—उपकर के आगम प्रथम मत: “038—केंद्रीय उत्पाद शुल्क—वस्तु मोटरगाड़ियों पर उपकर” याँच के अधीनभारत की संवित

मिथि में जमा किया जाएगा, और केंद्रीय सरकार, इस निमित संसद द्वारा सम्प्रक्रिया किए जाने के पश्चात, विकास आयुक्त को उत्तीर्ण गणि दे सकेगी जो वह आवश्यक समझे।

6. आता खोलना—उपनियम 5 के अधीन विकास परिषद द्वारा प्राप्त रकम, भारतीय स्टेट बैंक के खाते में रखी जाएगी।

7. विकास परिषद के लिए—(1) विकास परिषद, नियम 5 के अधीन अपने द्वारा प्राप्त रकम से संबंधित उचित लेखा जगाए रखेगा।

(2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखाओं का संपर्कालित विवरण और उसके संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।

8. विकास परिषद का बजट प्राप्तकालन:

(1) विकास परिषद, प्रत्येक वर्ष आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट तैयार करेगा और उसे मंजूरी के लिए केंद्रीय सरकार को उस तारीख को या उससे पूर्व प्रस्तुत करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनियित की जाए।

(2) जब तक केंद्रीय सरकार बजट को मंजूरी नहीं दे देती है तब तक कोई भी व्यय उपयत नहीं किया जाएगा।

(3) बजट ऐसे अनुदेशों के अनुसार तैयार किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जरूर किए जाएं।

9. विनियम प्रशासनिक व्यय—विकास परिषद, नियम 5 के अधीन अपने व्यय प्राप्त रकम के दो प्रतिशत से अनधिक राशि का उपयोग, कायालिय स्थापन और उपस्थित, लेखन सामग्री, डाक भैंसूल, टेलीफोन, तार, टेलेफॉन, मर्चिनियलय में नियोजित कार्यक्रम, रिक्विएट की मजदूरी और भर्तों, सरस्यों के यात्रा और वैदिक महे व्यय, और परिषद के अधिवेशन करने से संबंधित व्यय पूरा करने के लिए कर सकेगा।

उत्पादकाल

(नियम 5 विविधा)

मोटर गाड़ी उपकर नियम, 1984 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली मासिक विविधा का तारा

कारखाने का नाम

पता

उपकर के अधीन रहने हुए मात्र का आवि विविधा

उपकर के अधीन रहने हुए विनियम माल

उपकर के अधीन हड्डा गए मात्र

वर्णन	मात्रा	वर्णन	मात्रा	वर्णन	मात्रा
1	2	3	4	5	6

अन्त अनिश्चय

वर्णन	मात्रा	वर्णन	मात्रा
7	8	9	

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने ऊर व्यापक विविधियों का अरने/हमारे कारबाने के अप्रियों और वहियों से मिलान कर लिया है और वे, जहाँ तक मैं/हम अधिनियम करता हूँ/करते हैं, महे और पूर्ण हैं।

तारीख.....

विविधा

विनियमाना के हस्ताक्षर

[एक. सं. 8(8)/83-ए ई आई(i)]
के० प्रम. वैयं, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Heavy Industry)
NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 1984

S.O. 389 (E).—The following draft of certain rules which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 30 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is hereby published, as required by subsection (1) of that section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of sixty days from the date on which the Gazette containing the said notification is made available to the public.

Any objections or suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft within the period so specified will be considered by the Central Government. Such objections or suggestions should be addressed to the Secretary, Ministry of Industry (Department of Heavy Industry), Udyog Bhawan, New Delhi : 110011.

DRAFT RULES

1. **Short title.**—These rules may be called the Automobile Cess Rules, 1984.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires—

- (a) 'Act' means the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951);
- (b) 'cess' means the cess levied and collected in terms of notification No. S.O. 932(E), dated 28-12-1983 of Department of Heavy Industry issued under sub-section (1) of section 9 of the Act;
- (c) 'Collector' means the Collector of Central Excise and includes the Additional Collector of Central Excise, the Deputy Collector of Central Excise, Assistant Collector of Central Excise and Superintendent of Central Excise;
- (d) 'Development Council' means the Development Council for Automobile and Allied Industries established under Section 6 of the Act;
- (e) 'Automobile' means motor cars, buses, trucks, jeep type vehicles, vans, scooters, motorcycles, mopeds and all other automobiles covered under the sub-heading (5) of the First Schedule to the Act;
- (f) words and expressions used herein and not defined but defined in the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) or the rules made thereunder, shall have the meanings respectively assigned to them in that Act or the rules.

3. **Application of Central Excises and Salt Act** and the rules made thereunder.—Save as otherwise provided in these rules, the provisions of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the rules made thereunder including those relating to refund of duty, shall, so far as may, apply in relation to the levy and collection of the cess as they apply in relation to the levy and collection of the duty of excise on manufacture of automobiles under the Act and the rules.

4. **Submission of returns.**—(1) Every manufacturer shall submit to the Collector and to the Development Council on or before the 10th of every month a return in the Form specified in the Annexure to these rules of all stocks of items of automobiles manufactured or produced in, and removed from his undertaking during the previous month.

(2) If any manufacturer fails to furnish the return within the date specified in sub-rule (1) or furnishes a return which the Collector or the Development Council has reason to believe is incorrect or defective, the Collector may serve notice on the manufacturer calling upon him to produce all or any of his accounts relating to the automobiles manufactured or produced by him.

5. **Proceeds of the cess.**—The proceeds of the cess shall first be credited to the Consolidated Fund of India under the head '038—Union Excise Duties—Cess on Commodities Automobiles', and the Central Government may after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, hand over to the Development Council such sums as it may consider necessary from out of such proceeds after deducting therefrom the cost of collection.

6. **Opening of Accounts.**—The amount received by the Development Council under Rule 5 shall be kept in an account with the State Bank of India.

7. **Accounts of the Development Council.**—(1) The Development Council shall maintain proper accounts relating to the amount received by it under Rule 5.

(2) The audited statement of accounts for every financial year, together with the auditor's report thereon, shall be submitted to the Central Government.

8. **Budget Estimates of the Development Council.**—(1) The Development Council shall in each year prepare a budget for the ensuing financial year and submit the same for sanction to the Central Government on or before such date as may be specified by the Central Government.

(2) No expenditure shall be incurred until the budget is sanctioned by the Central Government.

(3) The budget shall be prepared in accordance with such instructions as may be issued from time to time by the Central Government.

9. Prescribed administrative expenses.—The Development council may utilise a sum, not exceeding 2 per cent of the amount received by it under Rule 5, to meet its expenses on account of office establishment and equipment, stationery, postage, telephones,

telegrams, telex, wages and allowances of staff employed in the secretariat, travel and daily allowance of members, and expenditure connected with heading of Council meetings.

ANNEXURE

(See Rule 5)

FORM OF MONTHLY RETURN TO BE SUBMITTED UNDER THE AUTOMOBILES CESS RULES, 1984

Month ending.....

Name of Factory.....

Address.....

Opening balance of good, subject to cess		Goods subject to Cess manufactured		Goods subject to cess removed	
Description	Quantity	Description	Quantity	Description	Quantity
1	2	3	4	5	6
Closing balance					
Description	Quantity		Remarks		
7	8		9		

I/We declare that I/We have compared the above shown particulars with the records and books of my/our factory and that they are in so far as I/We ascertain, accurate and complete.

Fate.....

Signature of Manufacturer

[F. No. 8(8)/83-AE(I)]
K. S. BAINS, Jt. Secy.